KUMARl SELJA : It does not directly come out of the question we are answering. So, I would require a separate notice for this question. But, since the hon. Member has asked a general question, I can also give him a general reply. The Yashpal committee went into the question of load and the burden. We have discussed this at several levels. It was discussed recently with the States. In the Central Advisory Board on Education there was a 'very exhaustive discussion. All the State Education Ministers took part in the discussion. It has gone back to the States. They have bean asked to hold a widespi'ead discussion in the States and then come back.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI : But you are spending time in discussing, discussing and discussing. Why can't you, for heaven's sake, implement something?

SHRI VENOO SHARMA : The hon. Minister has stated that liberal marking will be adopted. But those questions which were not within the purview of the syllabus and were not known to the students, they might not have attempted. Because the question paper was lengthy and the time was short, they might not have been able to complete their questions. Because those questions might not have been attempted, even this liberal marking will not help. WiU the Minister kindly explain how the liberal marking will help' them or will some grace marks in this context be given to the students?

KUMARl SELJA : May I reiterate once agaio that nothing was found to be out of syllabus in the question. But we have admitted that some questions were a little lengthy and we feel that the new marking scheme—as one of the hon. Members here himself expressed satisfaction—will be helpful in this ragard.

SHRI VENOD SHARMA : Mr. Chair man, Sir, I want to know if they will give some grace in marking to the students, be cause the liberal marking____

MR. CHAIRMAN : Liberal marking includes grace marks. The hon. Minister has also said that nothing was out of the syllabus. *{Interruptions)* Anyway, it is a liberal attitude. What we need in my view is that those who set the question papers should be more competent. This is something which we have forgotten.

KUMARl SELJA : We will take care on that.

DR. NAUNIHAL SINGH : Mr. Chairman, Sir, in another instance, may I know from the Minister whether it is a fact that one question of 25 marks was missing from the Class XII Hindi typewriting examination paper conducted in March, 1994 the Central Board of Secondary Education ? If so, what is the action taken by the Government to rectify this lapse ? May I know from the Minister whether someone has been punished for this act of omission ? What are the measures contemplated by the Government to avert such a situation in future ?

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लघु-सिंचाई परियोजनाओं पर अपेक्षाकृत कम लागत आना

*461. श्री अनंत जोशी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की तुलना में लघु परियोजनाओं पर प्रति हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पैदा करने के मामले में अपेक्षाकृत कम लागत आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए सिंचाई क्षमता पैदा करने के लिए पृथक-पृथक क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केवल प्रत्यक्ष निवेश को देखते हुए, लघु सिंचाई योजनाओं की प्रति हेक्टेयर लागत वृहद और मध्यम परियोजनाओं की तुलना में कम हो सकती है। तथापि, यदि लघु सिंचाई योजनाओं में नलकूपों/पंप सेटों को विद्युत चालित करने के संसाधनों की आनुपातिक लागत को ध्यान में रखा जाए है तो लघु योजनाओं की प्रति हेक्टेयर लागत वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की तुलना में कम नहीं है। इसके अलावा, वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का उपयोगी जीवन लघु योजनाओं से अधिक होता है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) में देश में वृहद व मध्यम सतही जल सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 5.1 मिलियन हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 10.7 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गयी है।

(घ) आठवीं योजना (1992—97) के लिए, वृहद व मध्यम परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के वास्ते सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय क्रमशः 22415 करोड़ रुपए और 5977 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, लघु सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए संस्थागत निदेशों के माध्यम से 5119 करोड़ रुपए जुटाए जाने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड'

*465. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' के विस्तार हेतु शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए किन्हीं जिलों का पता लगाया है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 1987-88 से लेकर 1993-94 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता :—

(रु० लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल सहायता
1	2
आंध्र प्रदेश	11394.78
अरुणाचल प्रदेश	403.68
असम	4080.08
बिहार	13600.82
गोवा	163.53
गुजरात	3529.11
हरियाणा	616.34
हिमाचल प्रदेश	2130.39
जम्मू और कश्मीर	1607.00
कर्नाटक	6482.58
केरल	613.57
मध्य प्रदेश	7055.66